have aimed at accelerating the overall industrial production. These includes rationalisation and simplification of tariff structure, reduction of the import and excise duties, increase in the central plan allocation for infrastructure, stimulus to the aggregate demand by increased plan outlays, increase availability of credit by reduction of Statutory Liquidity Ratio and reduction of minimum lending rates on commercial advances.

Industrial Township at NOIDA by JICA

583. SHRI SHANTI TYAGI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Japanese International Cooperation Agency (JICA) is negotiating with the Government to establish an ideal industrial township in NOIDA;

(b) if so, whether a preliminary report has been submitted to Government by the JICA on the NOIDA project; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) With a view to set up, if found feasible, an industrial model town in India, Japan International Cooperation Agency (JICA) is conducting a Master Plan study of various sites including NOIDA. Interim Report has been submitted by JICA. No decision about the selection of site has been taken.

Production Target for 1992-93

584. SHRI IQBAL SINGH:
SHRI SURESH PACHOURI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the industrial production targets fixed for 1992-93 and actual production;

(b) what are the reasons for decline in industrial production;

(c) whether the cement industry is in the grip of recession; and

(d) if so, the measures taken to accelerate the growth of the industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) No overall annual targets for industrial production are fixed by this ministry.

(b) According to the Quick Estimate of the Index of Industrial Production, the overall rate of growth of industrial production during 1992-93 was 1.3% as against growth rate of (—) 0.2% recorded in 1991-92.

(c) The actual production of cement in 1992-93 was 54.14 MT compared to the target of 56.5 MT. The shortfall in production is attributed mainly to sluggish market conditions and demand constraints.

(d) The cement industry has been delicensed and control on price and distribution has been removed. The Government is however, constantly reviewing the performance of the cement industry and providing infrastructural support such as supply of coal, railway wagons etc. on priority basis. Assistance for modernisation and technological upgradation of industry to improve its competitiveness is also provided.

Simplification of Regulatory Regime

585. SHRI IQBAL SINGH:
SHRI SURESH PACHOURI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether all the State Governments have announced rationalisation and simplification of the administrative and regulatory regime in tune with Centre's New Industrial Policy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what has been the response of industrialists thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) Union Government had suggested to all the State Governments to announce appropriate industrial policies in order to attract industries to their respective States. As per information available, the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa,

Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal have announced industrial policies after July, 1991.

उत्तर प्रदेश में उद्योग

586. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में 1989 तथा 1991 के दौरान स्थापित किए गए बड़े, मध्यम, लघु तथा अति लघु उद्योगों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में उनकी अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) आशय पत्रों के लिए अप्रैल, 1991 के अंत तक लम्बित पड़े प्रस्तावों, 1991-92 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों तथा 1 मार्च, 92 को लम्बित प्रस्तावों की संख्या कितनी-कितनी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही): (क) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित भारी, मझोले तथा कुटीर उद्योगों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
1. भारी तथा मझोले उद्योग	50	159	155
2. लघु उद्योग	26039	30246	33046
3. कुटीर उद्योग	24308	18504	6068

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान दो उद्योग तथा 1991-92 में एक उद्योग उत्तर प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया गया था। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग केवल निजी क्षेत्र में स्थापित किये गये थे।

(ग) 1989 से 1993 (जून तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये 507 आशय पत्र मंजूर किये गये थे। वर्ष 1991, 1992 और 1993 (जून तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये 345 औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हुए थे। 1-7-93 की स्थिति के अनुसार इन 345 आवेदनों में से 124 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पेश संकट

587. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही): (क) और (ख) 31-3-1992 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के 17 ऐसे उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से सरकारी क्षेत्र के 10 उद्यम घाटा उठा रहे हैं और इन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रुग्णता की परिभाषा के तहत रुग्ण घोषित किया गया है और उनमें से 9 उद्यमों को नवीकरण/पुनर्स्थापना सम्बन्धी योजनाएं बनाने हेतु औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में सीमेन्ट का उत्पादन

588. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीमेन्ट फैक्टरियां अपनी उत्पादन क्षमता का तीस प्रतिशत उत्पादन ही कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही): (क) उत्तर प्रदेश के चार सीमेंट कारखानों में से दो का क्षमता उपयोग 30% से अधिक है। 1992-93 और चालू वर्ष के दौरान चार संयंत्रों का वास्तविक उत्पादन और क्षमता उपयोग दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) क्षमता के कम उपयोग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रबंधकीय तथा वित्तीय समस्याएं, पुरानी प्रौद्योगिकी आदि।

(ग) क्षमता के अधिकाधिक उपयोग के लिए कारगर उपाय करना प्रबंधकों का कार्य है। तथापि सरकार कोयले के पर्याप्त तथा रेलवे माल डिब्बों की आपूर्ति सुनिश्चित करके सीमेंट संयंत्रों को सभी प्रकार की आधारभूत सहायता दे रही है।

विवरण

1992-93 और 1993-94 (अप्रैल-जून) के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े सीमेंट एककों का उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार रहा है :—